न्यूज डायरी

बंधकों की रिहाईः ट्रंप ने पाक, अफगानिस्तान का जताया आभार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पाकिस्तान/वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से फोन पर बातचीत की और दो बंधकों अमेरिकी केविन किंग और ऑस्ट्रेलियाई तिमोथी वीक्स की रिहाई के लिए धन्यवाद दिया। तालिबान ने इन दोनों को 2016 से ही बंधक बनाया हुआ था। मंगलवार को, केविन किंग (63) और तिमोथी वीक्स (50) को अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत जाबुल में अमेरिकी सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। इसके बदले में अफगान सरकार ने तीन बड़े तालिबानी कैदियों को रिहा किया। रिहा किए गए हक्कानी नेटवर्क से जुड़े तालिबान के तीन सदस्य अनस हक्कानी, हाजी माली खान और हाफिज राशिद हैं। वाइट हाउस ने कहा कि गुरुवार को ट्रंप ने दो अलग–अलग कॉल किए। वाइट हाउस ने बातचीत का ब्योरा बताते हुए कहा कि खान के साथ फोन पर बातचीत में, ट्रंप ने दो बंधकों की रिहाई में पाकिस्तान के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

चीन की बेल्ट रोड परियोजना पर भारत की चिंताओं को साझा करता है अमेरिका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। अमेरिका ने चीन की महात्वाकांक्षी ''वन बेल्ट वन रोड'' (ओबीओआर) परियोजना पर भारत के विरोध का समर्थन करते हुए कहा है कि वह इस पर नयी दिल्ली की चिंताओं को साझा करता है। साथ ही, उसने (चीन की) इस पहल के पीछे मौजूद आर्थिक औचित्य पर भी सवाल उठाये हैं। भारत ओबीओआर का विरोध करने वाला विश्व का एकमात्र बड़ा देश है। भारत ने अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर इस परियोजना का विरोध किया है। यह 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (सीपीईसी) पकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। ओबीओआर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका मकसद एशियाई देशों,अफ्रीका ,चीन और यूरोप के बीच सड़क संपर्क को बेहतर करना है।

बॉलिवुड, क्रिकेट भारत–अफगानिस्तान संबंधों के असल सितारे

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वॉशिंगटन। अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत रोया रहमानी ने कहा कि बॉलिवुड और क्रिकेट अफगानिस्तान के भारत के साथ संबंधों के असल सितारें हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संस्कृतियों के बीच गहरा संबंध है। रहमानी ने गुरुवार को एक समारोह में कहा, 'यह मानना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच संबंधों के ये 2 असल सितारे हमारे लोगों को निकट लाने में जितने प्रभावशाली रहे हैं, उतनी प्रभावी कोई सरकारी पहल भी नहीं हो सकती। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, श्मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रही। सच्चाई यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों पर कोई भी चर्चा बॉलिवुड और क्रिकेट का जिक्र किए बिना अधूरी है। रहमानी ने कहा कि वह जिनते अफगानिस्तानियों को जानती हैं वे सभी इन फिल्मों के कारण थोड़ी–बहुत हिंदी जानते हैं।

इमरान ने नवाज शरीफ की बीमारी की मंच से उड़ाई खिल्ली

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने को गंभीर रुप से बीमार बता रहे थे, एक समय ऐसा आया कि डॉक्टरों ने कहा कि यदि उनको इलाज के लिए लंदन नहीं ले जाया गया तो उनकी जान को खतरा है। कभी भी उनकी जान जा सकती है। इस वजह से उनको एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाया जाए। मगर जब उनको लंदन जाने वाले जहाज में चढ़कर जाते हुए देखा तो हैरान रह गया। वो दौड़ते–भागते हुए विमान में चढ़ रहे थे। इस दौरान उनके चेहरे पर एक अलग ही रंगत दिखाई दे रही थी। उनकी चढ़ाई को देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर लंदन जाने वाले जहाज को देखकर ही उनकी बीमारी दूर हो गई।

चीन नहीं चुन सकता दलाई लामा का वारिस

हकदार

■दलाई लामा का वारिस कौन हो यह चुनने का हक उन पर विश्वास करनेवालों को होः ब्राउनबैक

दलाई लामा के वारिस के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को विचार करना चाहिएः अमेरिका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। दलाई लामा के वारिस पर फैसला करने के चीन के दावे को खारिज करते हुए अमेरिका ने कहा कि यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उठाया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के विशेष राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक ने संवाददाताओं से कहा कि दलाई लामा का वारिस कौन हो यह चुनने का हक उन पर विश्वास करनेवालों को ही होना चाहिए।

ब्राउनबैक ने दलाई लामा के वारिस पर कहा, कई लोग ऐसे हैं जो चीन में नहीं रहते, लेकिन दलाई लामा का अनुसरण करते हैं। वह विश्वभर के एक जानेमाने धार्मिक नेता हैं, वह सम्मान के हकदार हैं और उनके वारिस को चुनने की प्रक्रिया उन पर विश्वास करने वाले समुदाय के हाथों में होनी चाहिए।' ब्राउनबैक ने इस पर चीन के दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अमेरिका दबाव बनाएगा।

ब्राउनबैक बीते दिनों धर्मशाला में थे जहां उन्होंने तिब्बती समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र को उनके वारिस के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को इस पर विचार करना चाहिए। अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। यूरोपीय देशों की सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि चीन क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने पंचेन लामा के साथ क्या किया। वह क्या कदम उठाना चाहते हैं इस बारे में हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जरूरत है कि हम पहले ही इस मामले को देख लें।' उन्होंने कहा कि दलाई लामा के वारिस को चुनने का अधिकार तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या किसी सरकार का नहीं। ब्राउनबैक ने कहा कि यह तो ऐसा होगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहे कि अगले पोप के बारे में फैसला लेने का अधिकार उसका है। यह अधिकार उसका नहीं है, यह फैसला लेने का अधिकार तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का है। उन्होंने कहा, 'चीन की सरकार ने बार–बार यह कहा है कि यह उसका अधिकार है। आप याद कीजिए कि उन्होंने पंचेम लामा को अगवा कर लिया था...अब हमें यह तक पता नहीं है कि वह जीवित भी हैं या नहीं। अब चीन की सरकार यह कह रही है कि वारिस का चयन उसके जरिए होना चाहिए।'

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अमेरिका चिंतित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिका ने पाकिस्तान में उत्पीड़न और बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने सहित वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के विशेष राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक ने कहा कि पाकिस्तान के हालात को लेकर हम चिंतित हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही।

ब्राउनबैक ने कहा, 'हम पाकिस्तान के बारे में चिंतित हैं। हम खासतौर पर वहां उत्पीड़न के कड़े माहौल और बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटनाओं को देखते हुए चिंतित हैं। अहमदिया मुसलमान देश में अपने धार्मिक रीति–रिवाज नहीं कर सकते क्योंकि वे (पाकिस्तानी) उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते।'

उन्होंने कहा,'हम विचार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति के लिए हम क्या कर सकते हैं।' एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रशासन विकास के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक संगठनों के साथ संपर्क में है और यह जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या वे खासकर उन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की मदद कर सकते हैं, जहां उनका उत्पीड़न किया जा रहा हो। उन्होंने कहा,'हम खास समूहों की सहायता कर रहे हैं जैसे कि हम कुछ देशों में खासतौर पर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं।

खालिस्तान समर्थक संगठन ने इमरान खान को दिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लंदन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ब्रिटेन के कुछ सिख संगठनों ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। करतारपुर कॉरिडोर के लिए इमरान खान के योगदान को देखते हुए संगठनों ने यह अवॉर्ड उन्हें दिया है। इन संगठनों में ब्रिटेन में काम कर रहा खालिस्तानी मूल का संगठन सिख फेडरेशन–यूके भी शामिल है। यह अवॉर्ड गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाशपर्व के अवसर पर लंदन के सिटी हाल में आयोजित एक समारोह में दिया गया। यूके और यूरोप में व्यापारिक मामलों के प्रवक्ता साहबजादा जहांगीर ने इमरान की तरफ से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

ऑस्ट्रिया में हिटलर के जन्मस्थल का अब पुलिस करेगी इस्तेमाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को अंतरिम मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जो अगले संसदीय चुनाव तक सरकार का संचालन करेगा। मंत्रिमंडल में 16 सदस्य हैं। राष्ट्रपति के भाई महिंदा राजपक्षे (74) और चमल राजपक्षे (77), 2 तमिल भाषी और एक महिला इसमें शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि यह एक अंतरिम सरकार है।

अगले हफ्ते होगा मंत्रिमंडल का विस्तारः उन्होंने बताया कि राज्यमंत्रियों की नियुक्ति अगले हफ्ते की जाएगी। राष्ट्रपति होने के नाते राजपक्षे मंत्रालयों को अपने पास नहीं रख सकते हैं, लेकिन वह मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं। नए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पद पर महिंदा राजपक्षे को नियुक्त किया गया है। उन्हें रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है जबकि चमल राजपक्षे के पास व्यापार एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय का प्रभार है।

फरवरी 2020 के बाद हो सकते हैं चुनावः मार्क्सवादी विचारधारा के नेता 70 वर्षीय गुणवर्द्धना को विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला संसदीय चुनाव अगस्त 2020 के बाद होना है।

प्रधानमंत्री को केवल तब ही हटाया जा सकता है जब उन्होंने इस्तीफा दिया हो, लेकिन गोटबाया की जीत के बाद नए संसदीय चुनाव की जरूरत महसूस होने लगी है ताकि नए राष्ट्रपति अपनी सरकार का गठन कर सकें। गोटबाया वर्तमान संसद को भंग कर फरवरी 2020 के बाद समयपूर्व चुनाव करवा सकते हैं।

आर्थिक गलियारे को लेकर यूएस ने पाक को दी एक और चेतावनी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। अमेरिका ने एक बार फ्घिर चीन और चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को लेकर पाक को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान इस समझौते पर अपने कदम पीछे नहीं खींचता तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। उसे दीर्घकालिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। यह तय है कि अगर अमेरिका ने सख्त रूख अपनाया तो बदहाल पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिका के इस रूख से भारत के दृष्टिकोण को समर्थन मिला है। भारत शुरू से ही इस परियोजना का विरोधी रहा है। इसकी कई वजहें रही हैं। गुरुवार को एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ऐलिस वेल्स ने कहा कि चीन–पाकिस्तान के इस आर्थिक गलियारे का मकसद दक्षिण एशिया में चीन की महत्वाकांक्षा है। वह इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका में रहने की ख्वाहिश रखता है। राजनयिक ने कहा कि इस करार से पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इससे केवल बीजिंग को ही लाभ होगा। उन्होंने पाकिस्तान को इसके एवज में एक बेहतर मॉडल की पेशकश की है।